

प्रेषक,

आर.के. सुधाशु,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण विभाग उत्तराखण्ड
इल्हासी-नैनीताल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 66 जनवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण विभाग हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9786/डीटीईयू/0202/पु0वि0/116/2014-15, दिनांक 02.12.2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/ XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्रशिक्षण विभाग की अतिरिक्त आवश्यकताओं के दृष्टिगत अनुदान संख्या-16 के आयोजनेत्तर पक्षान्तर्गत निम्न तालिकानुसार रु0 290000 हजार (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखते हुये संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रुपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
2230- श्रम तथा रोजगार	
03- प्रशिक्षण	
003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	
03- दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान	
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान	29000
योग	29000

(रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार किया जाय। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्पोरमेन्ट रूलस 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार के अधीन उपरोक्त उल्लिखित तालिका में इंगित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा जायेगा तथा संलग्न बी०एम०-9 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 189 (NP)/XXVII(5)/ 2014-15, दिनांक: 22 दिसम्बर 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोपरि।

महदीय
(अनूप के. सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी-नैनीताल।
4. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
6. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
अनुसचिव।